

Chief Minister's Information System
General List of Budget Announcements 2019-20 as on 27/07/2020

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
1	BAV19 WRD04 60000	46.0.0(2019-2020 (Vote on Account)) (13/02/2019) इंदिरा गांधी फीडर (राजस्थान क्षेत्र), मुख्य नहर एवं प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रु 812 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों को टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।	इन्दिरा गांधी फीडर (बुर्जी 496 से 671) तथा बुर्जी 0 से 620 तक एवं प्रणाली की नहरों के जीर्णोद्धार के कार्यों के 805.27 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों पर जून, 2020 तक 617.20 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके हैं। इन्दिरा गांधी फीडर की बुर्जी 496 से 520 तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अनूपगढशाखा, सूरतगढशाखा एवं रावतसर ब्रांच तथा अन्य वितरिकाओं एवं उप वितरिकाओं का कार्य प्रगति पर है। Task in Progress	21/03/2021
2	BAV19 WRD04 50000	45.0.0(2019-2020 (Vote on Account)) (13/02/2019) राजस्थान फीडर (पंजाब क्षेत्र) एवं सरहिन्द फीडर के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु 20 दिन पहले ही राजस्थान, पंजाब एवं केन्द्र सरकार के मध्य MoU हस्ताक्षरित हुआ है। इस अनुबंध के अंतर्गत इन नहरों के जीर्णोद्धार हेतु रु 1 हजार 976 करोड़ 73 लाख के कार्य आगामी तीन से चार वर्ष में संपादित कराये जायेंगे। जिससे इंदिरा गांधी एवं भाखड़ा प्रणाली के किसानों को सिंचाई हेतु बेहतर जल उपलब्ध होगा।	उक्त घोषणा की वर्तमान स्थिति बजट घोषणा बिन्दु संख्या 55.0.0; 2019.2020 (Modified Budget) के अनुसार है। अतः इस घोषणा को क्रियान्वित समझा जावे। Task Completed	Task Completed
3	BAM19 WRD06 80300	68.03.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) Eastern Rajasthan Canal Project एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसकी लागत रु 37 हजार करोड़ से अधिक है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में पानी की	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.)रु— परियोजना की डी.पी.आर तैयार की जाकर केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु भेजी जा चुकी है। परियोजना की लागत राशि रु. 37247.00 करोड़ रूपये है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है। ई.आर.सी.पी. के अन्तर्गत नवनेरा	31/03/2021 31/03/2020 (R)

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
		<p>कमी एवं भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार से इस परियोजना को national project का दर्जा देकर इसके क्रियान्वयन में अपेक्षित भूमिका निभाने की पुरजोर अपील की गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु अपनी हिस्सेदारी के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।</p>	<p>बैराज के निर्माण हेतु मार्च 2020 तक राशि रु. 67.33 करोड़ का व्यय किया जा चुका है व वित्तीय वर्ष 2020-21 में 175.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।</p> <p>Project Posed for Funding</p>	
4	BAM19 WRD05 90000	<p>59.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019)</p> <p>राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए इस वर्ष 21 जिलों- बूँदी, बारां, कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, करौली, सीकर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर एवं अलवर में रु 517 करोड़ के 55 कार्य शुरू किये जायेंगे।</p>	<p>राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 14 कार्य हेतु राशि रु 179.8413 करोड़ की स्वीकृति नाबार्ड से तथा 8 कार्य हेतु राशि 22.87 करोड़ की स्वीकृति Water Cess मद में वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुई। इन 20 कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। इन कार्य में से दो कार्य क्रम: नन्द समन्द एवं बुढा तीथ तालाब का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।</p> <p>29 कार्य हेतु राशि 248.70 करोड़ के प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु प्रेषित किये गये थे जिनमें से 28 कार्य राशि रु 214.37 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।</p> <p>शेष 4 कार्य में से 1 कार्य कोटडी बांध लघु सिंचाई परियोजना) तथा 1 कार्य (खमेरा नहर के इनटेक व लिंक टनल का कार्य) वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को भिजवाया जाना है व कामां पहाड़ी ड्रेन की चैन 350 से 800 तक डिसिल्टिंग व सुदृढीकरण का कार्य मनरेगा के तहत प्रगतिरत है एवं 1 कार्य (सजोला माईनर) RWSLIP योजनान्तर्गत श्शभरतपुर फीडरश्श के कार्य मे समाहित हो जाने के कारण पृथक से करवाये जाने की आवश्यकता नही है।</p> <p>Task in Progress</p>	31/03/2020 31/12/2022 (R)

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
5	BAM19 WRD05 80000	58.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) राज्य में कुल 211 बड़े बांध हैं। इनके जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधों हेतु बांध 'पुनर्वास एवं सुधार परियोजना' (DRIP) के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजे जायेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल रु 965 करोड़ का व्यय होना संभावित है, जिसके लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।	वित्त विभाग की आईडी संख्या 109004165 दिनांक 23.09.2019 के क्रम में परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट DEA&GOI को निर्धारित प्रपत्र में DEA&GOI के पोर्टल पर बाह्य सहायता हेतु अपलोड कर दी गई है। Task Completed	Task Completed
6	BAM19 WRD05 70000	57.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) 'राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना' के तहत अब 13 जिलों-भरतपुर, धौलपुर, टोंक, पाली, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में 29 सिंचाई उप-परियोजनाओं हेतु रु 262 करोड़ 40 लाख के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।	जायका से वित्त पोषित आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी. के तहत 29 उप-परियोजनाओं में से 8 उप परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं एवं 19 उप परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। शेष 2 में से 1 उप परियोजना की निविदा जुलाई, 2020 में आमंत्रित की जाएगी, तथा शेष 1 गंग कैनल उप परियोजना की डीपीआर बनाये जाने का कार्य प्रगतिरत है। Task in Progress	31/03/2020 31/12/2022 (R)
7	BAM19 WRD05 60000	56.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) इस वित्तीय वर्ष में 'राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना' द्वारा 22 हजार 831 हेक्टेयर water logged area (सेम क्षेत्र) को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए रु 207 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इससे पाकिस्तान में जा रहे हमारे पानी को भी रोकना संभव हो सकेगा।	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना की अनुमानित लागत रु. 3291.63 करोड़ है एवं अवधि 13.02.2018 से 12.02.2023 है, इसमें सेम समस्या निराकरण के लिए 298.31 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना को तीन ट्रेंचेज में विभक्त किया गया है। सेम समस्या के निराकरण का कार्य ट्रेंचेज द्वितीय में करवाया जाना निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना हेतु राशि रु. 207.13 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है।	Task Completed

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
			Task Complete	
8	BAM19 WRD05 50000	55.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर की मूल प्रवाह क्षमता पुनः स्थापित करने हेतु सरकार ने पंजाब एवं भारत सरकार के साथ IGNP नहर के जीर्णोद्धार हेतु MOU किया है। इससे सीपेज के नुकसान में कमी से जल की बचत होगी और आगामी पाँच सालों में अंतिम छोर तक किसानों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस योजना हेतु रु 1 हजार 976 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें से इस वर्ष में रु 220 करोड़ 37 लाख खर्च होंगे।	राजस्थान फीडर (पंजाब क्षेत्र) की रिलाईनिंग के कार्यों के लिए राशि रु 1305.267 करोड़ का प्रोजेक्ट एस्टीमेट स्वीकृत है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 60 प्रतिशत (रु. 726.25 करोड) सहायता की सहमति दी गई है । सरहिन्द फीडर (पंजाब क्षेत्र) की रिलाईनिंग के कार्या के लिए राशि रु 671.478 करोड का प्रोजेक्ट एस्टीमेट स्वीकृत है जिसमें राजस्थान का हिस्सा रु 307.87 करोड़ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 60 प्रतिशत (रु. 171.41 करोड) सहायता की सहमति दी गई है । पंजाब,राजस्थान एवं केन्द्र सरकार के मध्य दिनांक 23.01. 2019 को MOU पर हस्ताक्षर किये गये है। राजस्थान द्वारा पंजाब को इन कार्या के मद में रु 118.83 करोड का भुगतान किया जा चुका है। सरहिन्द फीडर में नवंबर, 2019 में क्लोजर लेकर सर्वाधिक क्षतिग्रस्त 16.67 किमी. लंबाई में रि-लाईनिंग कार्य किया जा चुका है। राजस्थान फीडर में रि-लाईनिंग कार्य वर्ष 2020 में मार्च-जून की नहर बंदी में लगभग 30 किमी. के कार्य पंजाब द्वारा करवाये जाने प्रस्तावित थे किन्तु वैश्विक महामारी कोरोना से नहर बन्दी स्थगित होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुए। आगामी नहर बंदी में कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। Task in Progress	31/03/2023
9	BAM20 19WRD 302000 0	302.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (Hon'ble CM Reply on 29/07/2019) भादरा तहसील के 15 बारानी गांव तथा नोहर तहसील के 14 बारानी गांव, जो कि सिद्धमुख नहर परियोजना की नोहर	डी.पी.आर बनाई जा चुकी है। Task Completed	Task Completed

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
		फीडर एवं सहवा लिफ्ट कैनाल से वंचित रह गये थे, को भी इस कमांड क्षेत्र में शामिल करने के लिए डीपीआर बनवायी जायेगी।		
10	BAM19 WRD26 60000	266.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (Hon'ble CM Reply on 16/07/2019) खो-मनसा बांध, उदयपुरवाटी का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जायेगा।	खो-मनसा माता बांध उदयपुरवाटी के कार्य की डी.पी.आर. बनाई जा चुकी है व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपए 436.25 लाख की दिनांक 10.02.2020 को जारी की जा चुकी है। चूंकी प्रस्तावित एनिकट की उंचाई 2 मीटर से अधिक है। अतः इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य था तथा यह स्वीकृति अभी 26.02.2020 को प्रदत्त की गई है। चूंकी डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित कार्य क्षेत्र वन भूमि में स्थित है अतः अब इसके संदक Diversion के online प्रस्ताव वन विभाग में आवेदित किए जा चुके हैं। Sanction Issued, but Task Not Started :	31/03/2020 31/10/2020 (R)
11	BAM19 WRD22 30000	223.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 31 मार्च, 2019 तक की बकाया सिंचाई कर की राशि 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।	संयुक्त शासन सचिव जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27(13)सि/38-।।।-।/1352 दिनांक 15.07.2019 द्वारा काश्तकारों का सिंचाई प्रभार जो कि दिनांक 31.03.2019 तक बकाया था को दिनांक 31.12.2019 तक एकमुक्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिए जाने की स्वीकृति पदान कर दी गई है। यह आदेश वित्त राजस्व विभाग की आई.डी. संख्या 11190050 दिनांक 12.07.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया गया है। Task Completed	Task Completed
12	BAM19 WRD13	134.14.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019)	RPSC द्वारा 317 पद ।मद सिविल/यांत्रिक के चयन हेतु मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं 458 कनिष्ठ सहायक पदों	31/03/2021

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Action Taken by Dept.	Deadline
	41400	प्रदेश में इस वर्ष जल संसाधन विभाग द्वारा 2000 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	<p>में से प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दिनांक 16.05.2020 द्वारा 435 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अभिशंषा के उपरान्त 415 अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः काउन्सलिंग के पश्चात् नियुक्ति दी जा चुकी है। 272 पटवारी भर्ती के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 05.12.2019 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है एवं 583 कनिष्ठ अभियंता, 61 कनिष्ठ प्रारूपकार, 68 अनुरेखक, 36 ड्राईवर के चयन हेतु अध्यक्ष, RSMSSB, दुर्गापुरा को रिक्त पदों की विज्ञप्ति शीघ्र जारी करवाने हेतु लिखा गया है। तदपश्चात् 13.02.20 को लैडैट द्वारा कनिष्ठ अभियंता भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 04.03.20 से 02.04.2020 तक ऑनलाइन भराये जा चुके हैं 135 कनिष्ठ सहायक एवं 16 स्टेनो की भर्ती अर्थना क्रमशः दिनांक 19.11.19 एवं 11.06.20 को ARD को भेज दी गई है। कनिष्ठ प्रारूपकार, अनुरेखक एवं पटवारी के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता नियमों में परिवर्तन हेतु थपसम राज्य सरकार को भिजवाई हुई है। कुल 1946 पदों के विरुद्ध 415 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है एवं शेष 1531 पदों हेतु चयन प्रक्रियाधीन है।</p> <p>Task in Progress</p>	